कार्यपालिक सारांश

कार्यपालिक सारांश

राजस्थान राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान की राजकोषीय स्थिति का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करती है।

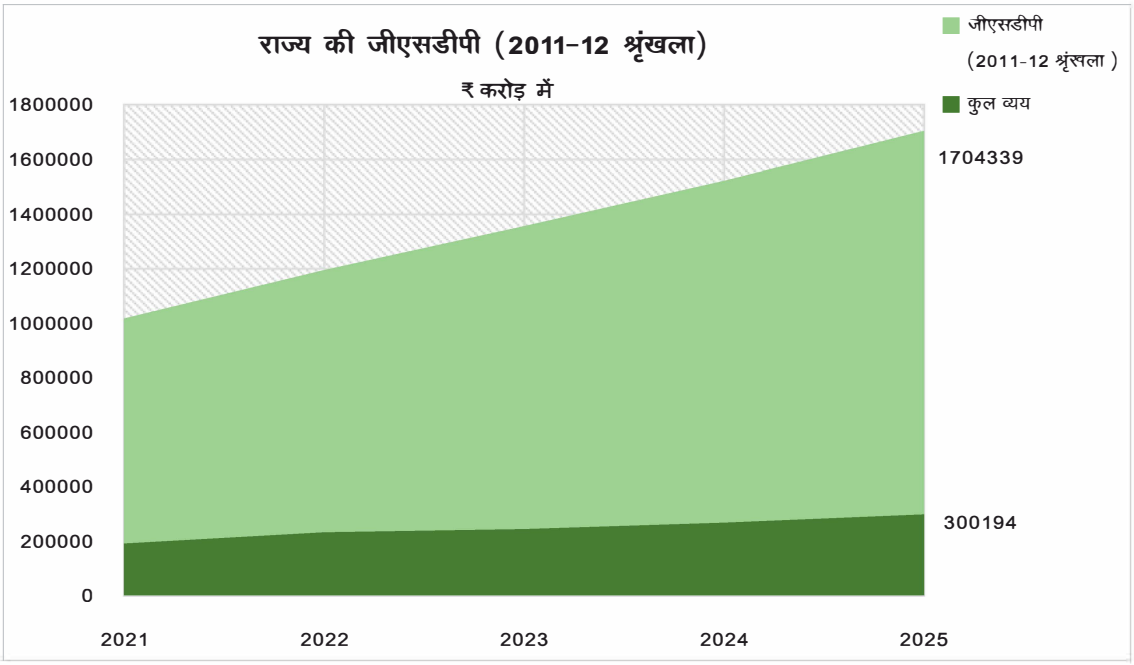

वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान, राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में पिछले वर्ष की तुलना में 12.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई,वित्त वर्ष 2023-24 में यह वृद्धि 12.17 प्रतिशत थी। राज्य की जीएसडीपी भारत की जीडीपी का 5.15 प्रतिशत है।

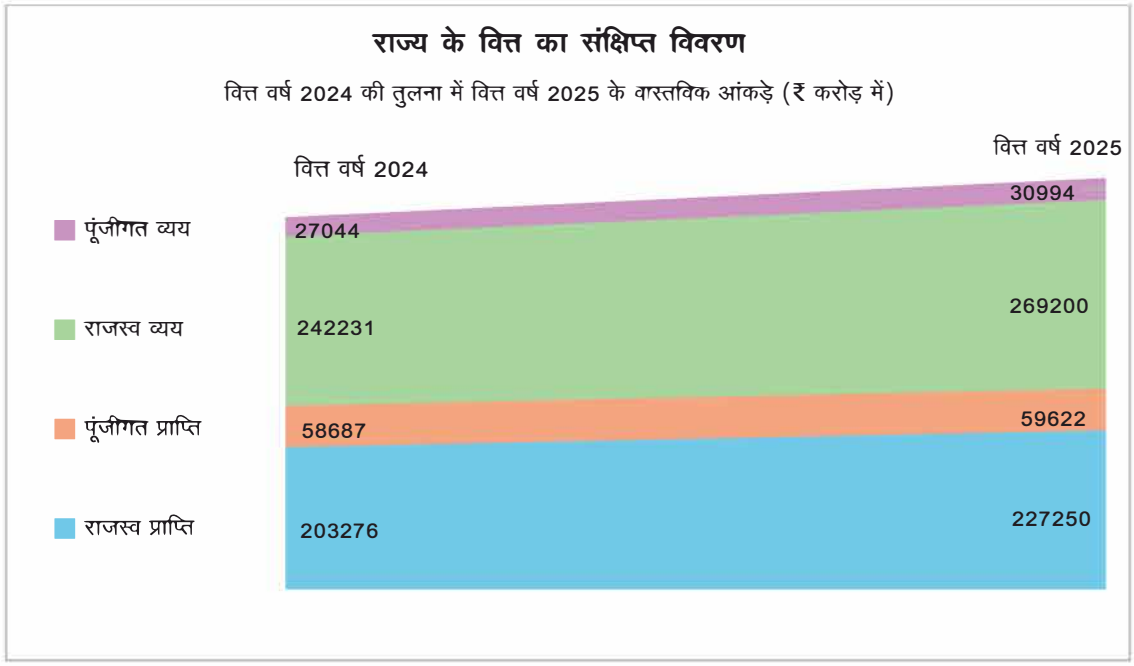

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों में वृद्धि के कारण 11.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य के व्यय में राजस्व व्यय की उच्च वृद्धि का प्रभुत्व रहा, जो प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी में वृद्धि के कारण हुई है।

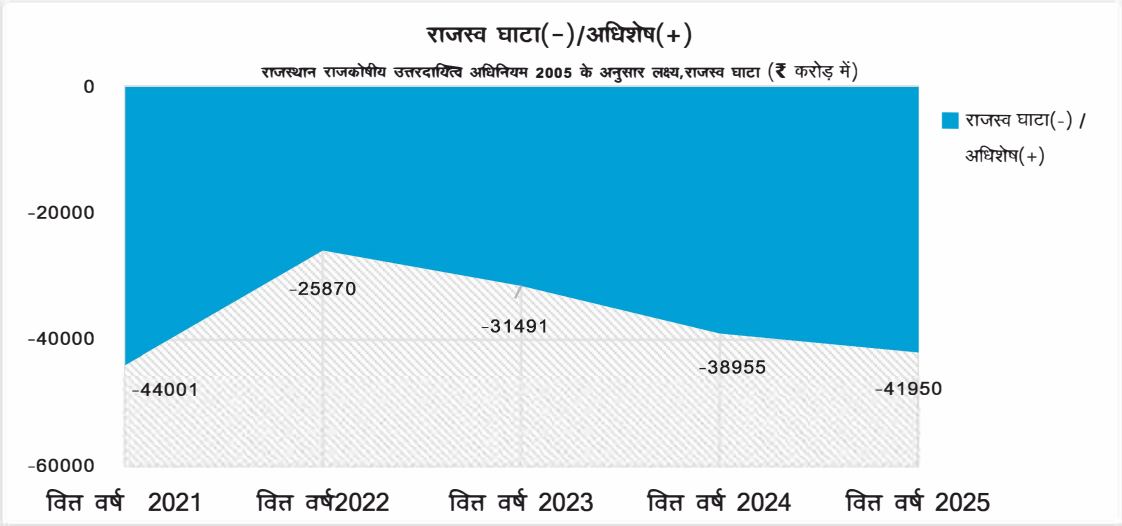

राजस्व घाटे में 7.69 प्रतिशत की वृद्धि वित्त वर्ष 2024 की तुलना में राजस्व व्यय में ₹ 26,969 करोड़ की वृद्धि और राजस्व प्राप्ति में ₹ 23,974 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। इससे राजकोषीय संभावना कम हो गई और इसलिए पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए बाजार से उधार बढ़ गया।

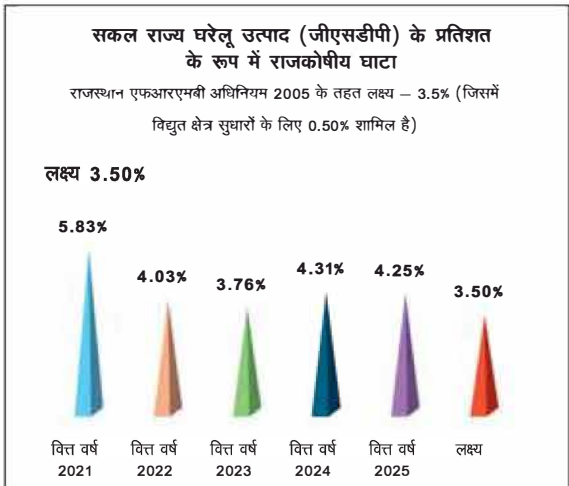

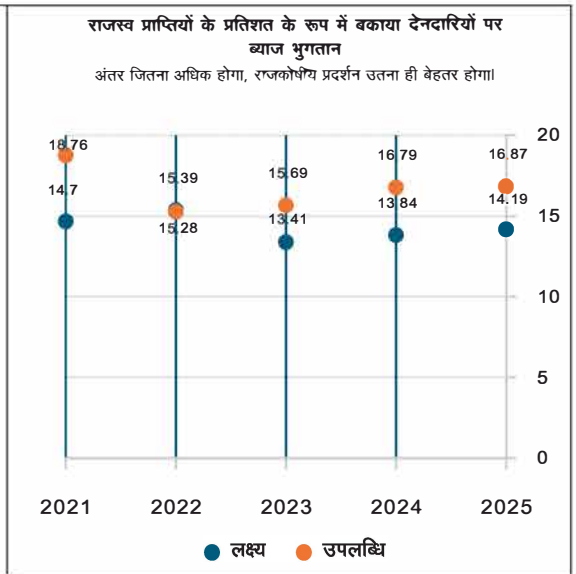

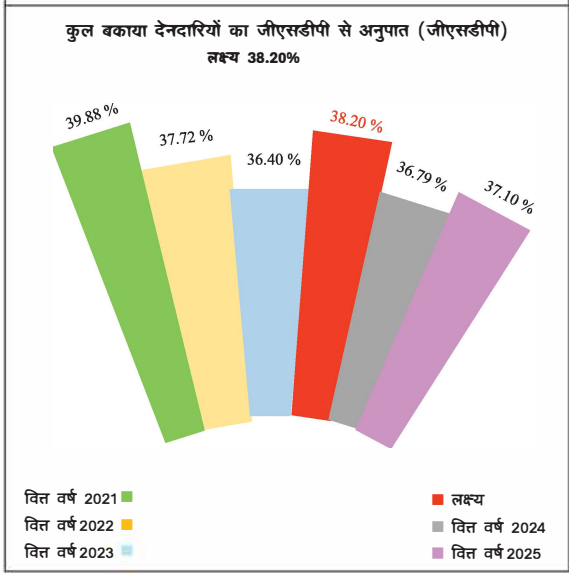

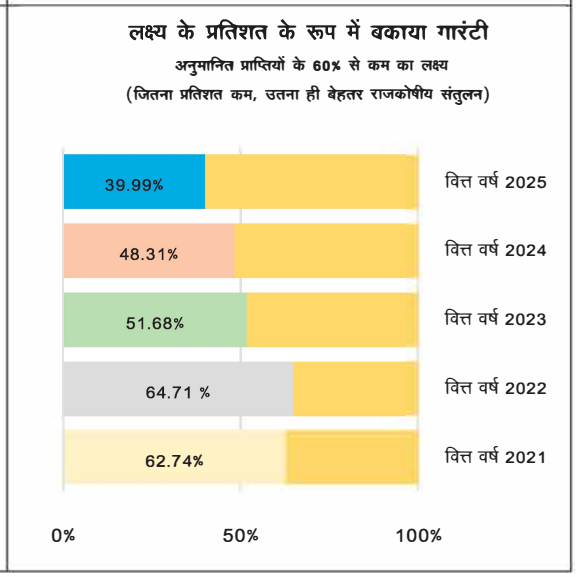

राज्य, राजस्व और राजकोषीय घाटे को राज्य के एफआरएमबी ढांचे के तहत निर्धारित मानकों के अन्दर नियंत्रित करने में असमर्थ रहा।, राज्य ने वित्त वर्ष 2024-25 में श्रम कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रम उपकार को, राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन कोष, राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष, जल संरक्षण उपकर, शहरी विकास उपकर कोष और ब्याज देनदारियों के संबंध में ₹ 437.04 करोड़ की महत्वपूर्ण बकाया देनदारियों को आगे बढ़ा दिया, जिससे राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा के आंकड़े परिवर्तित हो गए।

ऋण स्थिरता

वित्त वर्ष 2024-25

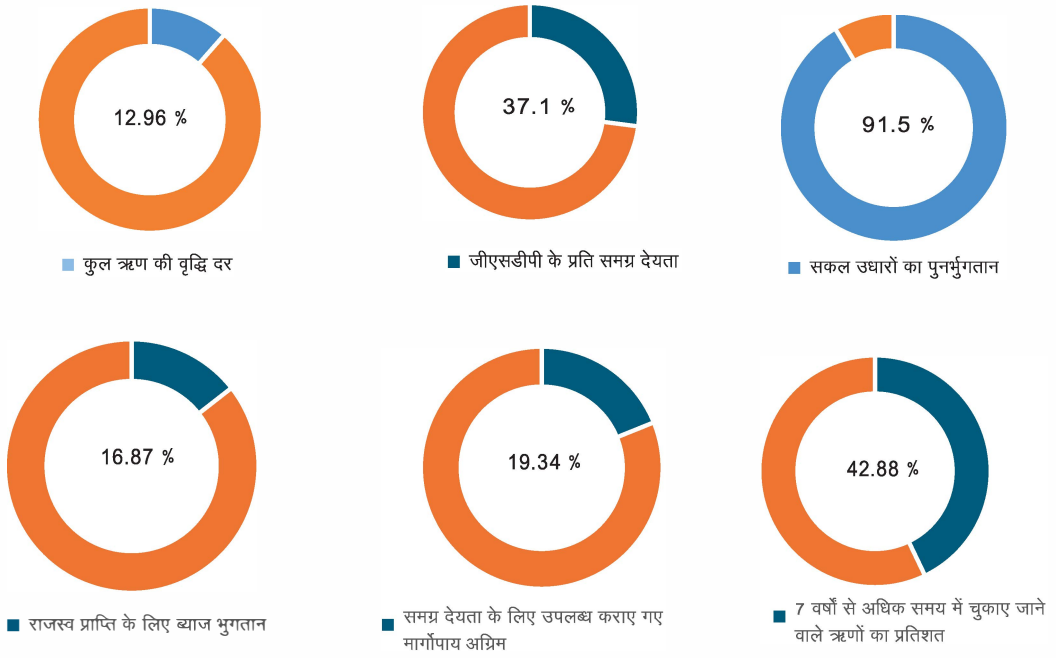

उच्च जीएसडीपी ऋण अनुपात यह दर्शाता है कि राज्य पर आर्थिक उत्पादन की तुलना में ऋण का बोझ काफी अधिक है और यह वित्तीय असुरक्षा तथा राजकोषीय लचीलेपन में कमी को इंगित करता है। राजस्व प्राप्ति के मुकाबले ब्याज भुगतान में वृद्धि एक अस्थिर ऋण प्रवृत्ति का संकेत देती है। अतः आने वाले वर्षों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

31 मार्च 2025 तक की वित्तीय जानकारी

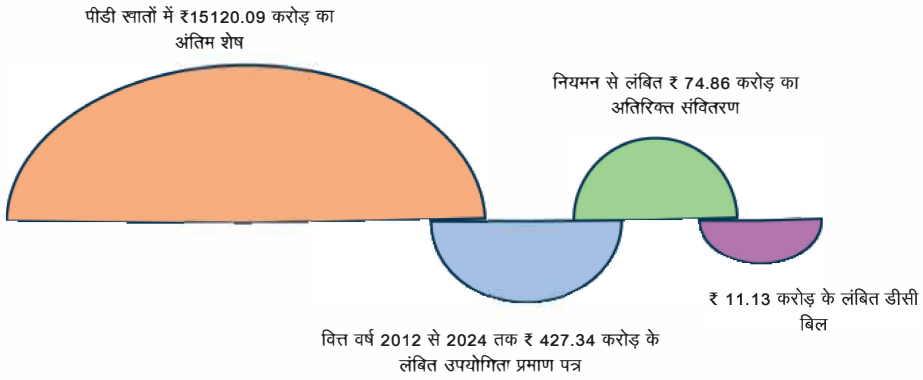

राजस्थान के राज्य वित्त का स्कोर कार्ड

उच्च प्राथमिकता संकेतक (राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005 के अनुसार)			
पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2024-25 का मूल्य	मानदंड (मापदंड)	टिप्पणी
राजस्व घाटा (जीएसडीपी का %)	2.46 %	≥ 0 (एफआरबीएम उद्देश्य)	एफआरबीएम का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है और लगातार बढ़ रहा है।
सकल राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का %)	4.25 %	≤ 3.5 % (एफआरबीएम सीमा) (बिजली सुधारों के लिए 0.5 % सहित)	एफआरबीएम का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है और लगातार बढ़ रहा है।
कुल देयतायें/ जीएसडीपी	37.10 %	< 38.20 % (एफआरबीएम उद्देश्य)	एफआरबीएम का उद्देश्य पूरा हुआ
बकाया गारंटी/ जीएसडीपी	6.85 %	कम रखें; गारंटी मोचन निधि का समर्थन प्रदान करें (सरकारी गारंटी नीति)	कम; गारंटी मोचन निधि द्वारा कवर किया गया आकस्मिक देयता जोखिम।

अन्य प्राथमिकता संकेतक

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2024-25 का मूल्य	मानदंड (मापदंड)	टिप्पणी
प्राथमिक शेष (जीएसडीपी का %) = (कुल प्राप्तियाँ – गैर-ब्याज व्यय) / जीएसडीपी	(-) 2.00%	> 0 बेहतर (आईएमएफ)	नकारात्मक संकेत यह दर्शाता है कि ऋण की स्थिरता को संभावित जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियां	16.87%	जितना कम हो उतना बेहतर; आरबीआई ने 15% से अधिक जोखिम की चेतावनी दी है (वित्त मंत्रालय)	उच्च,ब्याज के बोझ पर नजर रखने की जरूरत है।
ऋण सेवा / राजस्व प्राप्तियाँ (आरआर) (सार्वजनिक ऋण की मूल राशि + ब्याज) ÷ आरआर	27.51%	जितना कम हो उतना बेहतर; अगर यह लगातार 25% से अधिक हो तो निगरानी रखें (विश्व बैंक)	उच्च; संभावित वित्तीय असुरक्षा को दर्शाता है।
विकास-ब्याज अंतर (जी-आर) (वास्तविक जीएसडीपी वृद्धि - वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	5.08%	> 0 ऋण गतिशीलता का समर्थन करता है (आईएमएफ और डोमर मॉडल)	सकारात्मक बढ़त, हालांकि वित्त वर्ष 24 की तुलना में छोटी है। (7.24%)
पूंजीगत व्यय का हिस्सा = पूंजीगत व्यय ÷ कुल व्यय	10.32%	उच्च हिस्सेदारी = बेहतर गुणवत्ता मिश्रण (आरबीआई)	2023-25 में पूंजीगत व्यय की दिशा में बेहतर रुझान; पिछले 2 वर्षों में परिसंपत्ति सृजन में वृद्धि हुई है।
स्वयं की राजस्व क्षमता = राज्य का स्वयं-राजस्व ÷ राजस्व व्यय	47.11%	अधिक कवरेज बेहतर है (वित्त मंत्रालय)	राजस्व व्यय का लगभग 47% हिस्सा स्वयं-राजस्व से; शेष राशि हस्तांतरण/अनुदान के माध्यम से प्राप्त होती है।

राजस्थान की जीएसडीपी वृद्धि दर 12.02 प्रतिशत थी,जो जीडीपी वृद्धि दर 9.78 प्रतिशत से अधिक थी। हालांकि,उच्च राजस्व और राजकोषीय घाटा उच्च गुणक वाले पूंजीगत व्यय को बाधित करता है।

पिछले पांच वर्षों में राजस्व घाटे में लगातार वृद्धि के कारण घाटे और पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए बाजार से लिए गए ऋणों पर निर्भरता बढ़ गई है। इससे दीर्घकालिक ऋण स्थिरता के लिए संभावित जोखिम उत्पन्न होते हैं। लगभग ₹ 360.24 करोड़ की बकाया देनदारियों के संबंध में लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों से राजकोषीय संतुलन और भी जटिल हो गया है, जिससे राजकोषीय और राजस्व घाटे के और भी गहराने का खतरा है।

परिणामस्वरूप, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की वर्तमान दिशा को संभावित संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए संसाधन प्रबंधन में सावधानी और दक्षता की आवश्यकता होगी।